

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1173
दिनांक 10 फरवरी, 2020

ववादों पर विशेषज्ञ स मति

1173. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या देश में ववादों के चलते तेल और गैस क्षेत्र में लागत वसूली से लेकर उत्पादन लक्ष्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इससे माध्यस्थता के मामले बन रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्वेषण और उत्पादन से संबंधित ववादों को समयबद्ध संकल्प के लिए एक विशेषज्ञ स मति गठित करने का निर्णय लिया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैनाल की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और
- (घ) सरकार के इस कदम से माध्यस्थता कस हद तक कम होने और तेल और गैस क्षेत्र की लागत को बचाने की संभावना है?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग): अन्वेषण संबंधी क्रयाकलापों को बढ़ाने, घरेलू और वदेशी निवेश को आकृष्ट करने तथा सहजता से कारोबार करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 28.02.2019 की अधिसूचना द्वारा बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्तियों/वशेषज्ञों की एक स मति गठन करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने ववाद निपटान के लिए दिनांक 16.12.2019 की अधिसूचना द्वारा बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्तियों/वशेषज्ञों की एक स मति का गठन किया है।

स मति की प्रमुख शर्तें निम्नवत हैं:-

- i सदस्यों का कार्यकाल: स मति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- ii सदस्यों की शक्तियां और कार्य: स मति माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों के बीच ववादों के निपटान हेतु सुलह और माध्यस्थ कार्यवाहियां करने के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करेगी और यह प्रयास करेगी क स मति की पहली बैठक की तारीख से तीन माह के अंदर समझौता करार हो जाए।
- iii सुलहकर्ता और माध्यस्थ के तौर पर कार्य करने वाली स मति जब कभी अपेक्षित हो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद और सहायता के लिए तीसरे पक्षकार/वशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं ले सकती है।

- iv भारत के अन्वेषण ब्लॉकों/क्षेत्रों से संबंधित संवदाओं से उत्पन्न होने वाले कसी प्रकार के ववाद अथवा मतभेद को समिति को भेजा जा सकता है यदि संवदा करने वाले दोनों पक्षकार लखत में सुलह और मध्यस्थता के लिए सहमत हों और इस पर भी सहमत हो क इसके पश्चात मध्यस्थता कार्यवाहियों को चुनौती नहीं दी जाएगी।
- v ववाद निपटान से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, समिति सुलह/ मध्यस्थता की कार्यवाही करेगी। इस प्रकार की कार्यवाहियां निष्पक्षता, न्याय और पूर्ण ववेक के सिद्धांतों पर आधारित होंगी। प्रक्रियात्मक पहलू के लिए, समिति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग III में यथा उल्लिखित सिद्धांतों और वनियमों की सहायता ले सकती है।
- vi पक्षकार अपना मामला सुलहकर्ता अथवा मध्यस्थकर्ता के तौर पर कार्य करने वाली समिति के कर्मचारियों अथवा कार्यपालकों के माध्यम से समिति के समक्ष रखेंगे। अधवक्ता और परामर्शदाता सुलह कार्यवाहियों में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक क समिति यह नहीं पाती क कार्यवाहियों के संबंध में दायर कए गए आवेदन में कुछ कानूनी प्रकृति से जुड़ा कोई मुद्दा है अथवा ववादाधीन कोई ऐसा मुद्दा जिसके लिए उच्च वशेषज्ञता की जानकारी अपेक्षित हो और अधवक्ता अथवा परामर्शदाता द्वारा उसका स्पष्टीकरण/व्याख्या अपेक्षित हो और वे इस बात का ध्यान रखेंगे क ऐसी मदद अथवा भागीदारी के अभाव में सुलह अथवा मध्यस्थता की कार्यवाही में पक्षकार के हितों की बात पर्याप्ततः नहीं रखी जाएगी।
- vii पक्षकार सुलह अथवा मध्यस्थता की सूचना की तारीख से कसी दावों और प्रति-दावों पर समझौता करार होने तक, यदि कोई हो, कोई ब्याज का दावा नहीं करेंगे।
- viii समिति के समक्ष सुलह अथवा मध्यस्थता कार्यवाहियों पर समिति, तृतीय पक्षकार/वशेषज्ञ एजेंसी के सदस्यों के शुल्क सहित खर्च की गई समस्त लागत और व्ययों को पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन कया जाएगा। तथापि, अधवक्ता अथवा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए अनुरोध करने वाला पक्षकार ऐसे अधवक्ता अथवा परामर्शदाता द्वारा लया जाने वाला शुल्क वहन करेगा।
- ix मध्यस्थता अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के लंबित रहने से समिति के सामने सुलह अथवा मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, भले ही सुलह अथवा मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के समान वषय-वस्तु/मुद्दे पर हो।

घ. यदि संवदा के दोनों पक्षकार सुलह अथवा मध्यस्थता के लिए लखत रूप में सहमत होते हैं और आगे मध्यस्थता की कार्यवाही नहीं करने पर सहमत होते हैं तो पैनल/समिति की स्थापना से मध्यस्थता में कमी आएगी और समिति द्वारा सुलह अथवा मध्यस्थता की कार्यवाही से तेल और गैस क्षेत्र को इसकी लागत बचेगी।
